साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 11-17 नवंबर 2024 वर्ष-10, अंक-30

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

मध्यप्रदेश में मोहन राज! कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश में 254 नए खाद बिक्री केंद्र खोलेगी सरकार

» भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी सीएम ने मांगी

» सात दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी रीजनल इन्वेस्टर समिट

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। सिविल सेवाओं में महिला आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव पर आयोजित कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिला-पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात बेहतर होगा। दिवाली के बाद आयोजित मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी के साथ ही स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।

राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी है। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में होगा, जिसमें उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सात दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी।

» सिविल सेवाओं में अब महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण

» नए मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की भर्ती की आयु अब 50 वर्ष

» कालिदास सम्मान समारोह उज्जैन में होगा, उप-राष्ट्रपति आएंगे

141 खाद केंद्रों का संचालन विपणन समितियां करेंगी

मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट होने की खबरें आ रही है। इस संकट को दूर करने और किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। इनमें से 141 केंद्रों का संचालन विपणन समितियां करेंगी। इसके साथ ही 254 नए केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। नए केंद्रों की स्थापित पर एक करोड़ 72 लाख की सीमा तक की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

सारणी में नया थर्मल पॉवर प्लांट

सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में विस्तार करते हुए 660 मेगावॉट की नई थर्मल पॉवर इकाई लगाने का फैसला किया गया है। इस समय संचालित की जा रही 205 मेगावॉट और 210 मेगावॉट की दो-दो इकाइयों को डीकमीशन किया जाएगा और एक नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी।

समितियों का डिजिटाइज

राज्य में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों को कम्प्यूटरीकृत करके पैक समितियों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम होगा। इस आईटी परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें से 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।

मध्य प्रदेश में दिसंबर में होंगे निकाय और पंचायत के उपचुनाव

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उप-निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान नौ दिसंबर को होगा। नगरीय निकायों में नगर निगम रीवा में वार्ड-10 और नगर परिषद जैतहरी में वार्ड-6 के पार्षद पद के लिए निर्वाचन होना है। वहीं, पंचायतों में 4360 पंच और दो सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन-पत्र 18 नवंबर से लिए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र 25 नवंबर तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 26 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। मतदान नगरीय निकायों में सुबह सात से शाम पांच बजे तक और पंचायतों में सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा।

» प्रदेश में दो सरपंच और 4360 पंचों के लिए चुनाव होंगे

» नाम निर्देशन-पत्र 25 नवंबर तक लिए जाएंगे

» नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवंबर

» पंचायतों में मतदान दोपहर तीन बजे तक चलेगा

» पंच पद के लिए मतगणना तुरंत शुरू होगी

12 दिसंबर को मतगणना

मतगणना नगरीय निकायों में 12 दिसंबर को सुबह नौ बजे से होगी। पंच पद के लिए मतगणना मतदान केंद्र पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। सरपंच पद के लिए मतगणना 13 दिसंबर को विकासखंड मुख्यालय पर सुबह आठ बजे से होगी।

-केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किया ऐलान

किसानों को जहां दाम मिले वहां बेचें फसल, खर्च देगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदकर खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जा रहा। किसानों को जहां फसल का ज्यादा दाम मिले, वहां वे मंडी में जाकर बेच सकते हैं। उनके मंडी में आने-जाने का खर्च सरकार उठाएगी। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में विजयपुर मंडी प्रांगण में आयोजित चुनावी सभा के दौरान की। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस फुस्सी बम है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गईं। कांग्रेस की सरकार इतने समय तक रही, लेकिन बहनों के खाते में कभी

एक रुपया नहीं डाला। भाजपा सरकार द्वारा बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपए डाले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान महिला आरक्षण को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि बहनों-बेटियों को शासकीय नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का हमारा जो संकल्प था, उस पर अमल किया गया है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्रदेश पर लगातार बरस रहा है। विजयपुर में भी जनता को यह विश्वास है कि विकास होगा तो भाजपा की सरकार ही करेगी।

वनों की उपज से शासन को एक साल में एक अरब 87 करोड़ का आय

निमाड़ के वनों में संजीवनी, देशभर में बढ़ी डिमांड

खंडवा। जागत गांव हमार

निमाड़ के वनों में संजीवनी है। क्योंकि जब भी बात जड़ी-बूटी की होगी तो यहां अधिकांश बीमारियों की दवा मौजूद है। वहीं, यहां की वनोपज से शासन के भंडार भी भरा रहे हैं। इस वर्ष औषधि, सागौन की बेशकीमती लकड़ियां, तेंदू पत्ता और महुआ सहित वनों से मिलने वाली वस्तुओं से एक अरब 87 लाख 10 हजार रुपयों की आय हुई है। प्राचीन काल में खंडवा को खांडव वन के नाम से जाना जाता था। क्योंकि यहां वन ज्यादा थे। यहां उगने वाले पेड़-पौधों में औषधियां भी है जिनकी डिमांड पूरे देशभर में रही है। आज भी यहां के वनों की स्थिति प्रदेशभर के वनों की अपेक्षा में अच्छी है। खंडवा से लगे बुरहानपुर, खरगोन व बड़वानी के जंगल शासन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहां के वनों से मिलने वाले तेंदू पत्ता, महुआ, सागौन, बांस व धावड़ा गोंद देशभर में प्रसिद्ध है। वहीं, वन में मौजूद औषधीय पौधे मनुष्य के दिल से लेकर दिमाग तक की बीमारियों को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। जैसे नीम,

निमाड़ के वनों में मौजूद औषधीय पौधों से मिलने वाली आय 10 लाख सालाना है। बाकी अन्य वनोपज से शासन को मिलने वाली आय एक अरब 87 करोड़ 10 लाख है। इसमें वन विकास निगम से होने वाली सालाना आय 50 करोड़ रुपए भी जुड़ी है।

रमेश गणावा, सीसीएफ, निमाड़

पलास, घुंघची, हरड़ा, बज्रदंती, चिरचिरा, कलौंजी, निर्गुन्डी, आंवला, भिलावा, दुग्धबेल व कोलू सहित अन्य पेड़-पौधे औषधि के रूप में काम आते हैं। निमाड़ में औषधीय पौधे माइग्रेन, गर्भपात, तपेदिक, कुष्ठ रोग, बवासीर, सर्पदंश व अन्य बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। इन पेड़-पौधों की कटाई कर दवाइयों के लिए भोपाल स्थित फार्मास्युटिकल लैब भेजा जाता है। देशभर में इनसे बनी औषधियों की डिमांड है।

बड़े होते हैं यहां के तेंदू पत्ते, इसलिए देशभर में मांग

वन अफसरों ने बताया जिले के वन की मुख्य आय जंगल का तेंदू पत्ता देशभर में प्रसिद्ध है। क्योंकि यहां बड़े पत्ते होते हैं। इसका स्वाद भी अन्य जिलों के पत्तों से बेहतर है। इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। इसके लिए बाकायदा वन विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर टेंडर जारी किए जाते है। जिसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों के व्यापारी बड़ी संख्या में पत्ता खरीदने के लिए भाग लेते हैं।

72587 महिला-पुरुषों को रोजगार भी मिला

जिले में तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए निमाड़ में वन्य ग्राम स्तर पर 33 समितियां बनाई गई है। निमाड़ में आदिवासी महिला-पुरुष संग्राहकों को साढे 20 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। खंडवा जिले में 38,902 पुरुष व 33,685 महिला आदिवासी संग्राहकों को रोजगार मिला है। इनका जीवन वन और उनसे होने वाली आय पर आधारित है।

अधिकारी ने मिठाई का डिब्बा और लिफाफा पूर्व पंचायत अध्यक्ष के मुंह पर फेंका

सीधी में जिला पंचायत सीईओ को घूस देना पड़ा भारी

सीधी। जागत गांव हमार

गत दिवस एक पूर्व पंचायत सदस्य अखिलेश कुशवाहा अपर कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ आईएएस अंशुमान राज के चैंबर में मिठाई का डिब्बा और नोटों से भरा लिफाफा लेकर पहुंच गए। जिसे राज ने लेने से इंकार करने के साथ ही उसे कुशवाहा के मुंह पर फेंक दिया। मामले में राज रिश्वत देने के प्रयास का केस भी दर्ज कराने वाले हैं। सीधी जिले में जिला पंचायत सीईओ के रूप में अंशुमान राज की पोस्टिंग हुई है, जहां उन्हें अपर कलेक्टर का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। सीईओ राज ने जैसे ही मिठाई का डिब्बा खोल तो उसके नीचे लिफाफे का एक पैकेट देखा। उन्हें मिठाई के डिब्बे को देखकर इस बात का अंदाजा लग गया कि इसमें मिठाई के डिब्बे के साथ पैसों का बंडल भी है। इसके बाद उन्होंने मिठाई का डब्बा अखिलेश कुशवाहा के मुंह पर फेंक दिया और खुद फोन करके कोतवाली थाना प्रभारी को सूचित किया। इसके बाद कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कुशवाहाको कोतवाली थाने ले गई जहां पूछताछ की जा रही थी।

तेज तर्रार छवि के हैं सीईओ

अंशुमान राज साफ सुथरे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वे तेज तर्रार हैं और कार्य के प्रति ईमानदार हैं। कई रोजगार सहायक और सचिव के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है। इस घटना के बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जांच के बाद होगी कार्यवाही

कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि हाल का यह मामला है। जहां जिला पंचायत सीईओ अंशुमान राज ने हमें जानकारी दी थी। इसके बाद दोनों व्यक्तियों को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी दोनों संदिग्ध व्यक्ति इस बात से इंकार कर रहे हैं। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के साक्ष्य और जिला पंचायत सीईओ के साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।

सिर्फ मिलने के उद्देश्य से गए थे सीईओ के पास

वहीं, पूरे मामले को लेकर अखिलेश कुशवाहा पूर्व जिला पंचायत सदस्य से ही बात की गई। तब उन्होंने बताया कि हम पहली बार जिला पंचायत सीईओ के पास गए थे। इसलिए अपने साथ मिठाई का डिब्बा लेकर गए थे और जो पैसे मेरे पास थे। वह पैसे मैंने अपने निजी कार्य के लिए रखे हुए थे, मैं उन्हें देने नहीं वाला था। जिला पंचायत सीईओ को गलतफहमी हुई है कि हम उन्हें रिश्वत देने के लिए गए हुए थे, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था।

एक ही स्थान पर मिलेगी खाद, बीज, मिट्टी से जुड़ी जानकारी

पीएम किसान समृद्धि केन्द्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीएम किसान समृद्धि केन्द्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें खाद, बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त खेती-किसानी से संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जायेंगी। उल्लेखनीय है कि 3 सितम्बर को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता विभाग और नर्मदा नियंत्रण मण्डल के कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये थे। पीएम किसान समृद्धि केन्द्रों का उद्देश्य है कि एक ही स्थान पर किसानों को मिट्टी, बीज, उर्वरक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। इसके साथ ही इन केन्द्रों को कस्टम हॉयरिंग सेंटर्स से जोड़कर किसानों को कृषि संबंधी छोटे और बड़े उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं। किसानों को कृषि की बेहतर पद्धतियों और विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की जाएं।

किसानों को मिलेंगे ये लाभ

ग्राम पंचायतों में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित हो जाने से किसानों को अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें केन्द्र में ही खेती-किसानी के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। संसाधन उपलब्ध न होने पर किसान समृद्धि केन्द्र समन्वयक की भूमिका निभाकर उन्हें संसाधन उपलब्ध कराएगा। इससे किसानों का खाद, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए आने-जाने का समय भी बचेगा और अन्य व्यय भी नहीं होंगे। उन्हें किसान समृद्धि केन्द्र पर ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे वे बेहतर उपज भी प्राप्त कर सकेंगे।

किसान समृद्धि केन्द्र पर रहेगी हेल्प-डेस्क

पीएम किसान समृद्धि केन्द्र पर हेल्प-डेस्क भी रहेगी। यहां से मृदा विश्लेषण और मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलेगी। केन्द्र से फसल बीमा, ड्रोन, कृषि वस्तुओं की जानकारी के साथ अधिक लाभार्जन के लिये फसलों के पेटर्न के पैकेज संबंधी जानकारी भी मिलेगी।

किसानों का रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप

पीएम किसान समृद्धि केन्द्र के संचालक कृषि विभाग और कृषि संबंधी कार्यक्रम और गतिविधियों से जुड़े रहेंगे। पीएम किसान समृद्धि केन्द्र से जुड़े प्रगतिशील किसानों के किसान समृद्धि समूह नामक व्हाट्स-अप ग्रुप का निर्माण भी किया जाएगा।

मप्र में इस साल धान का उत्पादन 72.4 लाख टन होने का अनुमान

धान की सरकारी खरीदी दो दिसंबर से शुरू की जाएगी

भोपाल। जागत गांव हमार

अच्छे मानसून के बीच इस साल मप्र में धान की फसल का बंपर उत्पादन होने का अनुमान है। केंद्र के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदेश में 2.25 लाख टन धान का अधिक उत्पादन अनुमानित है। हालांकि अधिक उत्पादन के बीच दाम नीचे चल रहे हैं। नॉन-बासमती चावल के दाम पिछले साल 3500 से 4000 प्रति क्विंटल के बीच थे, वो अभी 2500 से 3000 के बीच हैं। इस बीच अब किसानों को एक्सपोर्ट से ही सहारा मिलने की उम्मीद है। केंद्र ने हाल ही में नॉन-बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर से बैन हटा दिया है। मप्र में पिछले साल 70.22 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल यह उत्पादन बढ़कर 72.40 लाख टन होना अनुमानित है। इसकी मुख्य वजह धान का बढ़ता रकबा और इस साल बहुत अच्छा मानसून है। धान, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद के लिए कुल मिलाकर 7.85 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, जबकि पिछले साल 7.54 लाख किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था। धान की सरकारी खरीद 2 दिसंबर से होगी।

चावल के मूल्य अभी नीचे

प्रदेश की अलग अलग मंडियों में चावल के मूल्य 2600 से लेकर 3275 प्रति क्विंटल तक हैं। जबकि इसी अवधि में पिछले साल चावल के दाम 3500 से लेकर 4000 रुपए तक थे। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए रखा है। किसानों की मांग थी कि चुनावी वायदे के मुताबिक प्रदेश सरकार धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल में करे।

एकल नलजल योजनाओं का कार्य 31 दिसंबर तक करें पूरा: सचिव पीएचई

भोपाल। जागत गांव हमार

सचिव लोकसेवा यांत्रिकी विभाग पी नरहरि ने रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। नरहरि ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। एकल नलजल योजनाओं के कार्य 31 दिसम्बर तक हर हाल में पूरा करके लक्ष्य के अनुसार घरों में नल कनेक्शन दें। यह योजना आमजनता की स्वास्थ्य रक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा जल संरक्षण के उद्देश्यों में भी सहायक है।

सचिव नरहरि ने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। जिन एकल नलजल योजनाओं का कार्य 70 से 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है, उनके छूटे हुए कार्य 15 दिसंबर तक पूरे कराकर योजना ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करें। जनपद के सीईओ पूर्ण नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कराकर उनका संचालन कराएं। पानी की नियमित आपूर्ति होगी तो जल कर भी अवश्य मिलेगा। जल कर की नियमित प्राप्ति से ही पंप चालक के मानदेय तथा नलजल योजना से जुड़े छोटे-मोटे कार्य किए जाना संभव होगा। योजना संचालन के लिए हर गांव में ग्राम जल स्वच्छता समिति तथा महिला स्वसहायता समूहों को तैयार करें। दिसम्बर अंत तक रीवा और मऊगंज जिलों के 390229 घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करें।

बैठक में जल जीवन मिशन के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी ने जानकारी दी कि रीवा और मऊगंज जिलों में पांच बड़ी समूह नलजल योजनाओं का कार्य चल रहा है। इनमें से कंदैला योजना से 109 में से 106 गांवों में पानी दिया जा रहा है। शेष चार योजनाओं का कार्य मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद हर घर में नल से पानी की आपूर्ति होने लगेगी। बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद, कलेक्टर प्रतिभा पाल, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सपना त्रिपाठी, प्रमुख अभियंता केके सोनगरिया, मुख्य अभियंता एचएस गौड़ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले के ढाई लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

मंदसौर में गांधीसागर समूह जलप्रदाय योजना बनेगी 920 गांवों के लिए वरदान

वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। योजना से 2 लाख 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। आगामी दिसंबर 2024 तक योजना पूर्ण की जाकर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना से न सिर्फ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एवं सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीणों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उइके ने बताया कि पहले जहां हर साल गर्मी में पानी की गंभीर कमी होती थी और लोग जलस्रोतों के सूखने के कारण पानी की समस्या से जूझते थे, वहीं अब गांधीसागर बांध से जल आपूर्ति का एक स्थिर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस योजना से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को साकार किया जा रहा है।

समुदाय की सहभागिता और रोजगार सृजन

गांधीसागर जलप्रदाय योजना का उद्देश्य न सिर्फ पानी की आपूर्ति करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना भी है। इस योजना के तहत 1200 से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है और योजना के पूरा होने पर भी अन्य कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के समुचित संचालन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। ये समितियां जल आपूर्ति और इसके प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी, जिससे जल संकट का स्थायी समाधान और ग्रामीणों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार

यह योजना न सिर्फ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि जल जनित रोगों में कमी लाने और ग्रामीण समुदायों को स्वस्थ बनाने का भी काम करेगी। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाने से निजात मिलेगी और वह अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

बदलाव की बयार

गांधीसागर जलप्रदाय योजना मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद और स्थायी समाधान लेकर आई है। इस योजना से न सिर्फ जल संकट का समाधान होगा, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन के स्तर में भी सुधार होगा। जल आपूर्ति के इस महत्वाकांक्षी प्रयास के साथ, मंदसौर जिले में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो आने वाले समय में विकास और समृद्धि का प्रतीक बनेगा।

वन मुख्यालय ने सभी डीएफओ को भेजे निर्देश

प्रदेश में संरक्षित की जाएगी औषधीय गुणों से भरपूर खुरासानी इमली

धार के मांडू में पाई जाती है खुरासानी इमली

इस खास वृक्ष में वर्षा ऋतु में उगती हैं पत्तियां।

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में खुरासानी इमली को संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए इसकी खोज प्रदेश भर में की जाएगी। धार जिले के मांडू में पाए जाने वाले प्राचीन एवं सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष खुरासानी इमली की वनमंडलों में खोज करने के लिए वन मुख्यालय ने सभी डीएफओ को निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, 14वीं शताब्दी में महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान इसे मांडू लाया गया था और इसका नाम बाओबाब से बदलकर खुरासानी इमली कर दिया गया। इसे एक और नाम मांडव इमली से भी जाना जाता है। यह पेड़ ऐसा दिखता है, जैसे किसी ने इसे उल्टा करके लगाया हो। जड़ें ऊपर और तना नीचे, पत्तियां केवल वर्षा ऋतु में उगती हैं।

यह है खासियत

इसके फल को खाने के बाद तीन से चार घंटे तक प्यास नहीं लगती। इसकी उम्र पांच हजार वर्ष से भी अधिक हो सकती है। यह पेड़ अपने जीवन काल में लगभग एक लाख 20 हजार लीटर तक का पानी संग्रह कर सकता है। यह अपने खास स्वाद के साथ ही औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। बता दें कि धार जिला प्रशासन की अनुशंसा पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 11 खुरासानी इमली के पेड़ को हैदराबाद स्थित ग्रीन किंगडम नामक प्राइवेट कंपनी के बोटैनिकल गार्डन में ट्रांसलोकेट कर दिया गया था, जिसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है।

खुरासानी इमली की महत्ता को देखते हुए इसका संरक्षण किया जा रहा है। अब पूरे प्रदेश के वनमंडलों में यह प्रजाति कहां-कहां है और कितनी संख्या में है, इसकी जानकारी डीएफओ के माध्यम से एकत्रित की जा रही है।
-सुदीप सिंह, सदस्य सचिव, मप्र बायोडायर्सिटी बोर्ड

विरासत वृक्ष घोषित करने अधिसूचना होगी जारी

जैव विविधता वाले वृक्षों को काटने पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। राजस्व विभाग ने अपनी 14 मई 2024 की अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित वृक्षों को काटने, गिराने, घेरे जाने या अन्यथा क्षति पहुंचाने के लिए इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं, मप्र बायो डायवर्सिटी बोर्ड ने खुरासानी इमली को विरासत वृक्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

खरीदी केंद्रों में सोयाबीन की नमी के कारण धीमी प्रक्रिया

एमएसपी पर सोयाबीन बेचने में किसानों की रुचि नहीं

» अच्छे दाम की उम्मीद में किसानों ने सोयाबीन उपज रोकी

» 3.68 लाख टन सोयाबीन उपार्जन की मिली अनुमति

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन का उपार्जन किया जा रहा है लेकिन किसान इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 25 अक्टूबर से प्रदेश में एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी शुरू की गई है। अभी तक 600 किसानों ने ही लगभग 1000 टन सोयाबीन बेचा है जबकि इसके लिए 460 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। पंजीयन के माध्यम से अब तक 14,000 किसानों ने स्लाट बुकिंग कराई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाजार में समर्थन मूल्य के बराबर दाम मिलने के कारण किसानों ने उपज रोक रखी है। उनका अनुमान है कि आगे चलकर सोयाबीन की उपज के और अच्छे दाम मिल सकते हैं। इधर, खरीदी केंद्रों में सोयाबीन में नमी अधिक होने के कारण सैंपल लौटाए जा रहे हैं, इसके कारण भी

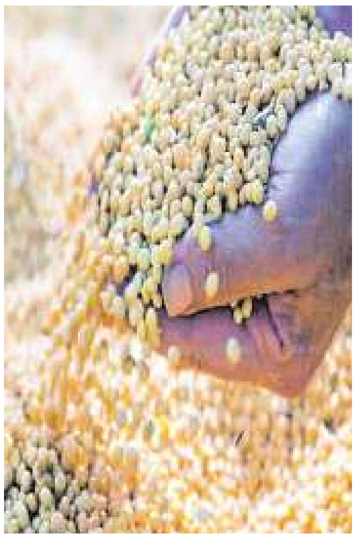

उपार्जन की गति धीमी है। दूसरी ओर बाजार में 4,500 से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,982 प्रति क्विंटल निश्चित है लेकिन इससे कम मूल्य बाजार में मिलने के कारण किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग की थी।

दाम बढ़ने की उम्मीद

प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 13. 68 लाख टन सोयाबीन के उपार्जन की अनुमति दी है। इसके लिए 3,43,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों को उम्मीद है कि भाव और बढ़ेंगे इसलिए अभी वह उपज को रोककर रख रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब सोयाबीन के दाने सूख रहे हैं। दीपावली का त्योहार भी हो गया है इसलिए खरीदी केंद्रों तक उपज आने में तेजी आएगी।

कुत्तों में एर्लिचियोसिस रोग कारण और सावधानियां

» डॉ. सुभ्रदल नाथ
» डॉ. संजू मंडल
» डॉ. गिरिधारी दास
» डॉ. सुमन कुमार
» डॉ. रूपेश वर्मा
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर,मध्यप्रदेश

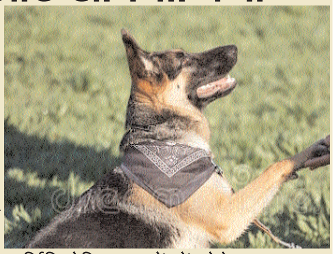

एर्लिचियोसिस श्वानों में होने वाला एक टिक जनित संक्रामक रोग है। यह रिकेट्सियल जीव से होता है। जिसमें सामान्यत: बुखार, भूख न लगना आदि लक्षण दिखाई देते हैं।

रोग कारक: एर्निचियाकैनिस (ई. कैनिस) श्वानों में एर्लिचियोसिस बीमारी की सबसे आम प्रजाति है। इसके अलावा भी अन्य प्रजातियां पाई जाती है। एर्लिचिया कुत्तों में कैसे सवंमित होता है। एर्लिचियोसिस सवंमित किलनी/टिक द्वारा कुत्तों में फैलता है। इसमें मुख्यत: ब्राउन डॉग टिक शामिल है। यह बीमारी सवंमित श्वानों से स्वस्थ कुत्तो में टिक के द्वारा फैलता है। संक्रमित टिक 5 महीने तक संक्रमण फैला सकता है।

एर्लिचियोसिस बीमारी के कुत्तों में लक्षण, प्रारंभिक लक्षण: बुखार,भूख न लगना, अवसाद, कमजोरी, शरीर में जकड़न, चलने में समस्या (लंगड़ापन), खांसी, श्वास लेने में दिक्कत, एनीमिया, रक्तचाप। **दीर्घकालिक लक्षण:** प्लीहा में सूजन, तंत्रिका संबंधी समस्याऐं, सूजे हुए अंग, लंबे समय तक बुखार।

परीक्षण: एर्लिचिया के लक्षण दिखाई देने के बाद पशुचिकित्सक से संपर्क करें। **पशु चिकित्सक निम्न परीक्षण/जाँचें करा सकता है-** पूर्ण रक्त कोशिका गणना, कम प्लेटलेटकाउंट, एनिमिया, एंटीबॉडी परीक्षण, एलिसा या पी.सी.आर, जीवाणु रक्त स्मीयर।

एर्लिचियोसिस का उपचार: इसके उपचार के लिए मुख्यत: एंटी प्रोटोजोअल दवांए दी जाती है। जैसे **-टेट्रासाइक्लीन** @22mg/kg bwt.(दिन में 3 बार दो हफ्ते तक, प्रारंभिक संक्रमण के दिनों में)।(दीर्घकालीन संक्रमण में 1-2 महीने तक) **डॉक्सीसाइक्लीन**-@5-10mg/kg bwt. (रोजाना 10-15 दिनों के लिए)। **ई.मिडोकार्ब**-@5-10mg/kg bwt. इसके अलावा अन्य सहायक दवांए भी दी जाती हैं। अधिक गंभीर मामलों में रक्ताधान की जरूरत पड़ सकती है।

एर्लिचियोसिस से बचाव/रोकथाम: इसका इलाज से बेहतर बीमारी की रोकथाम है। इसलिए कोशिश करें की अपने घर और कुत्तों को टिक्सफ्री रखें। समय समय पर कृमिनाशक (कीड़ों की दवाई) देते रहें। शरीर में किलनी (टिक) दिखने पर उसको हटा दें।

फसल के लिए पानी की खपत में लगातार वृद्धि बन सकती है बड़ी समस्या का कारण

ट्वेन्टे विश्वविद्यालय (यूटी) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में दुनिया की मुख्य फसलों को उगाने के लिए लोगों के द्वारा खपत किए जाने वाले पानी की मात्रा में ऐतिहासिक बदलावों पर प्रकाश डाला गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि फसल उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में लगातार वृद्धि जारी है, जो पहले से मौजूद अनेकों पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकती है।

अध्ययन में 1990 से 2019 के दौरान 175 फसलों को उनके हरे और नीले जल पदचिह्नों के आधार पर इसकी पड़ताल की है। हरा पानी यानी बारिश से आने वाला पानी है और नीला पानी सिंचाई और उथले भूजल से आता है।

शोधकर्ता ने शोध के हवाले से कहा, हमें इन दो तरह के पानी के प्रकारों के बीच अंतर करने की जरूरत है क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र और समाज में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं।

विश्लेषण की गई लगभग 80 फीसदी फसलों को 1990 की तुलना में 2019 में प्रति टन कम पानी की जरूरत पड़ी। हालांकि इस तरह की उत्पादकता के फायदे फसल उत्पादन के वैश्विक कुल जल पदचिह्न को बढ़ने से रोकने के लिए अपयाज्ञ्त थे। 1990 के बाद से, उत्तरार्द्ध में लगभग 30 फीसदी या 1.55 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। शोध में अनुमान लगाया गया है कि साल 2019 के लिए मुख्य रूप से हरे पानी का 6.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जो प्रति व्यक्ति हर दिन की खपत लगभग 2,400 लीटर है।

वृद्धि के पीछे के क्या कारण है: कुल वृद्धि का लगभग 90 फीसदी 2000 से 2019 के बीच हुआ, जिसे शोधकर्ता तीन मुख्य सामाजिक-आथिज़्क कारकों से जोड़ते हैं। सबसे पहले, तेजी होता वैश्वीकरण और आथिज़्क विकास ने विभिन्न आयातित फसलों और फसल उत्पादों की खपत में काफी वृद्धि की। दूसरा वैश्विक आहार अधिक पानी-गहन उत्पादों जैसे पशु उत्पाद, मीठे पेय और शकज़्रा और वसायुक्त खाद्य पदार्थों की ओर स्थानांतरित हो गया। तीसरा कई सरकारों के ऊजाज़् सुरक्षा और ग्रीन एजेंडे ने फसल-आधारित जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दिया।

इन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने अधिकतर ऐसी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जिन्हें कई तरह के उत्पादों जैसे खाद्य, पशु चारा, जैव ईंधन आदि में उपयोग किया जा सकता है। ये फसलें किसानों, निवेशकों और बीमाकर्ताओं को फसल उत्पादन से जुड़े वित्तीय खतरों को कम करने में मदद करती हैं क्योंकि अलग-अलग अंतिम-उपयोगकर्ता बाजार स्थिर मुनाफा और निवेश पर वापसी सुनिश्चित करते हैं।

सक्रिय कृषि करने वाले समूह के साथ मिलकर पिछले दशकों में इन फसलों का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए, केवल तीन सबसे बड़ी फसलें- तेल ताड़ के फल, सोयाबीन और मक्का 1990 से 2019 के बीच फसल उत्पादन के कुल जल पदचिह्न में कुल वृद्धि का आधा हिस्सा समझा जा सकता हैं।

फसल उगाने के लिए अधिक पानी का उपभोग: अध्ययन के अनुसार, भारत, चीन और अमेरिका सबसे बड़े पानी के उपभोक्ता हैं। हालांकि कुल जल पदचिह्न वृद्धि ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुई, जो अक्सर जगलों के काटे जाने और जैव विविधता के नुकसान सहित अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के साथ सामने आती है। यह अध्ययन एनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

शोधकर्ता शोध के हवाले से बताते है कि यह क्षेत्र फसल उत्पादन के लिए ज्यादा भौगोलिक परिस्थितियां प्रदान करता है जबकि अनुकूल कृषि नीतियां बड़े कृषि खाद्य निगमों से निवेश आकर्षित करती हैं। इसके कारण कुछ क्षेत्र अधिक पानी का उपयोग करने वाली फसलों की एक छोटी सी श्रेणी में तेजी से विशेषज्ञ बन गए, जैसे इंडोनेशिया में तेल ताड़ के फ्ल या ब्राजील में सोयाबीन और गन्ना।

भविष्य में क्या होगा? : शोधकर्ता ने शोध में कहा, आंकड़े बताते है कि आने वाले दशकों में लोग फसल उत्पादन के लिए पानी की खपत को बढ़ाते रहेंगे। अधिक फसलें पैदा होंगी, जिससे दुनिया भर में सीमित हरे और नीले जल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा। हालांकि यह एक अधिक आशावादी परिदृश्य हो सकता है।

शोधकर्ताओं ने शोध के हवाले से सुझाव दिया है कि फसलों को उगाने में पानी का उपयोग बढ़ाने, उत्पादन को कम पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने, कम पानी की खपत वाली खेती को व्यापक रूप से अपनाने और पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की आवश्यकता को कम करने में बहुत संभावनाएं हैं।

शोध दिखाता है कि हमारे सामने कई समस्याएं हैं और अब अधिक फसल के उत्पादन के लिए कम पानी का उपयोग संबंधी भविष्य के समाधानों पर काम करने का समय आ गया है।

पशु चिकित्सा में जैवसुरक्षा (बायोसेक्योरिटी) का महत्व

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आकाश सुमन
» डॉ. अनिल धाकड़
» डॉ. शिवराज चौहान
» डॉ. आकाश सेंगर
» डॉ. रोमेश राजोरिया
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू मध्यप्रदेश

पशु चिकित्सा में बायोसेक्योरिटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जो न केवल पशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। बायोसेक्योरिटी का अर्थ है उन उपायों का सेट, जिन्हें रोगों के प्रकोप से बचने और रोकने के लिए लागू किया जाता है। यह कृषि और पशुपालन में महत्वपूर्ण है, जहां एक छोटे से प्रकोप का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। बायोसेक्योरिटी के उपायों में संक्रमण को रोकने के लिए साफ-सफाई, आइसोलेशन, और उचित प्रबंधन तकनीकें शामिल हैं।

रोगों की रोकथाम: पशुओं में रोगों का फैलाव न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह पशुपालकों की आर्थिक स्थिरता पर भी बुरा प्रभाव डालता है। बायोसेक्योरिटी उपायों के माध्यम से, जैसे , नियमित स्वास्थ्य जांच, और संक्रमण नियंत्रण तकनीकें, हम रोगों के प्रकोप को काफी हद तक रोक सकते हैं।

एक अध्ययन में पाया गया है कि टीकाकरण के माध्यम से वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की रोकथाम में 70-90फीसदी तक की प्रभावशील हो सकती है।

मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा: कई पशु रोग मानवों में भी फैल सकते हैं, जिन्हें जूआनोटिक रोग कहा जाता है। बायोसेक्योरिटी उपायों से इन रोगों के प्रसार को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, बर्ड फ्लू जैसे रोगों का प्रसार रोकने के लिए पशु स्वास्थ्य की देखभाल करना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगभग 60प्रतिशत नए मानव रोग जूआनोटिक होते हैं, और इनसे बचाव के लिए बायोसेक्योरिटी उपाय अत्यंत आवश्यक हैं।

आर्थिक लाभ: जब पशु स्वस्थ होते हैं, तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। बायोसेक्योरिटी के उपायों को अपनाने से पशुपालक रोगों के प्रकोप को रोक सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है। स्वस्थ पशुओं से दूध, मांस, और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होती है। वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार, प्रभावी बायोसेक्योरिटी उपायों से पशुपालन में 20-30प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है।

फार्म प्रबंधन में सुधार: बायोसेक्योरिटी उपायों के कार्यान्वयन से फार्म प्रबंधन में सुधार होता है। यह पशुपालकों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने और उनकी देखभाल करने में मदद करता है। नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने से फार्म पर संक्रमण का खतरा कम होता है।

पोल्ट्री फार्म में जैव सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों का पालन करना आवश्यक है। सभी नए पक्षियों को फार्म में लाने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच करें और उन्हें अलग रखने का प्रावधान रखें। फार्म में प्रवेश करने से पहले सभी व्यक्तियों और उपकरणों को साफ करना और कीटाणुरहित करना चाहिए। नियमित रूप से फार्म के आसपास सफाई और डिसइन्फेक्शन करें ताकि बीमारी फैलने का खतरा कम हो सके। इसके अलावा, पक्षियों के खाने और पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दें और बीमार पक्षियों को तुरंत अलग कर दें। इन उपायों से आप अपने पोल्ट्री फार्म को सुरक्षित रख सकते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य का संरक्षण: जब एक फार्म में बायोसेक्योरिटी उपायों को अपनाया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल उस फार्म तक सीमित नहीं रहता। यह पूरे समुदाय पर भी असर डालता है। स्वस्थ पशु समुदाय का निर्माण करने से रोगों का प्रसार कम होता है, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र का स्वास्थ्य बेहतर होता है।

पशु चिकित्सा में बायोसेक्योरिटी का महत्व नकारा नहीं जा सकता। यह न केवल पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और आथिज़्क स्थिरता को भी प्रभावित करता है। बायोसेक्योरिटी उपायों को अपनाकर, हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

पशुपालकों और पशुचिकत्सकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे बायोसेक्योरिटी के महत्व को समझें और इसे अपने दैनिक प्रबंधन में शामिल करें। इससे न केवल पशुओं की देखभाल में सुधार होगा, बल्कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कृषि वातावरण का निर्माण भी संभव होगा।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- gaibriyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. डा. वीरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com,मोबा- 8827176184
6. डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. रोमा वर्मा, सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail. com, मोबा- 6267535371

अक्टूबर माह के शुरुआत में जमकर बारिश हुई, इसी समय सरसों की बोवनी की तैयारी होती है...

भिंड जिले के किसानों को गेहूं पर भरोसा, सरसों का रकबा घटा

भिंड। जागत गांव हमार

भिंड जिले के किसानों का इस बार सरसों से मोह भंग हुआ है। इसकी वजह अक्टूबर माह में हुई अतिवृष्टि है, क्योंकि अधिक बारिश होने की वजह से किसान समय पर अपने खेत तैयार नहीं कर सके। ऐसे में इस बार गेहूं की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। बता दें कि अक्टूबर माह के शुरुआत में जमकर बारिश हुई। सरसों की बोवनी के लिए खेत भी इसी समय तैयार किए जाते हैं। लेकिन बारिश की वजह से किसान चाहकर भी कुछ कर नहीं सके। इसके बाद हर साल की तरह डीएपी की किल्लत शुरू हो गई। कृषि विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार जिलेभर में 1.90 लाख हेक्टेयर में सरसों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से अब तक 1.60 बोवनी हो चुकी है। जबकि पिछले साल जिले में 2.17 हेक्टेयर में सरसों की बोवनी हुई थी। इसी तरह इस वर्ष 1.20 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हो चुकी है। जबकि वर्ष 2023 में 1.05 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी। इस बार जहां सरसों का रकबा घटा है, वहीं गेहूं के रकबे में वृद्धि हुई है। वहीं जिले में 800 हेक्टेयर में चना और 500 हेक्टेयर में मसूर की बोवनी होना है।

तापमान अधिक होने से दोबारा करनी पड़ रही बोवनी

नवंबर माह की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दिनों दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। इस वजह से जो किसान एक से डेढ़ महीने पहले सरसों की बोवनी कर चुके थे, उनमें से ज्यादा किसानों के खेतों में बीज का ठीक प्रकार से अंकुरण ही नहीं हुआ। इस वजह से किसानों को फिर से सरसों की बोवनी करना पड़ रही है। इन दिनों अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, जिससे दिन के समय मौसम में गर्माहट है। इस गर्माहट की वजह से जमीन में नमी कम हो रही है। इस वजह से सरसों का बीज भी झुलसने लगा है। ऐसे में किसानों को पुनः बोवनी करनी पड़ रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में 30 हजार हेक्टेयर में किसानों पुनः सरसों की बोनी करना पड़ी है।

अतिवृष्टि की वजह से इस बार पांच बीघा में सिर्फ गेहूं किए हैं, क्योंकि सरसों की बोवनी के लिए वर्तमान में दिन का तापमान भी अधिक है।
सेवक पुरवंशी, किसान ग्राम परा, तहसील अटेर

गेहूं के रकबे में वृद्धि हुई अक्टूबर माह में हुई बारिश के चलते इस बार जिलेभर में सरसों का रकबा कम हुआ है। जबकि गेहूं का रकबे में वृद्धि हुई है। किसान मौसम को देखते हुए खेतों में बोवनी करें।
- रामसुजान शर्मा, उपसंचालक कृषि भिंड

एक संपूर्ण ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया गया

खेड़ावदाः एक आदर्श स्वच्छ और आत्मनिर्भर गांव की कहानी

भोपाल । जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील का खेड़ावदा गांव आज पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन चुका है। यहां की ग्राम पंचायत ने गांव को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की हैं। स्वच्छता और साफ-सफाई के साथ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़कर, खेड़ावदा को एक संपूर्ण ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। उज्जैन जिले में 726 ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम है। ओडीएफ प्लस ग्राम की निरंतरता बनाए रखने हेतु ग्राम पंचायत में स्वच्छता के साथ अन्य घटकों को समाहित किया जा रहा है, जिससे एक स्वच्छ सुजल आत्मनिर्भर ग्राम निर्मित हो।

1 घर-घर कचरा संग्रहण वाहन

2. सूखा एवं गीला कचरा संग्रहण

गांव में स्वच्छता का जन अभियान

स्वच्छता को एक बार का काम मानने के बजाय, इसे ग्रामीणों की आदत में बदलने के लिए जन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत, बच्चों की टोलियां और महिलाओं के समूह गांव के घर-घर जाकर कचरे के पृथक्करण (सूखा और गीला) की प्रक्रिया को समझाते है। लोगों को समझाया कि सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग एकत्र करने से उनका निष्पादन आसानी से किया जा सकता है।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

पंचायत ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छ पेयजल का महत्व समझते हुए आरओ प्लांट और पेयजल टंकी की व्यवस्था की। गांव का कोई भी व्यक्ति मात्र 6 रुपए देकर पूरे महीने स्वच्छ पानी ले सकता है। इससे न केवल गांव के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ बल्कि पंचायत के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा।

शिक्षा में स्वच्छता का समावेश

ग्राम के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षकों ने नियमित रूप से बच्चों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाए, जिससे स्वच्छता का संदेश नई पीढ़ी में गहराई से उतरा।

कचरा प्रबंधन और रोजगार

ग्राम पंचायत ने बैंक से ऋण लेकर एक कचरा वाहन खरीदा और हर घर से कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की। एकत्रित कचरे को पृथक कर गीले कचरे से खाद तैयार की गई, जिसे गांव के किसान कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूखे कचरे को कबाड़ में बेचकर सफाईकर्मियों के मानदेय की व्यवस्था की गई। गांव के हर घर में डस्टबिन रखने के लिए प्रेरित किया गया ताकि लोग कचरे को खुले में न फेंकें।

स्वच्छता के ढांचे का निर्माण

ग्राम में सीसी रोड, सामुदायिक स्वच्छता परिसर और आरसीसी नालियों का निर्माण किया गया, जिससे बारिश के पानी की निकासी आसानी से हो सके। नालियों के अंतिम सिरे पर सामुदायिक सोक पिट बनाए गए जिससे पानी जमा न हो और सड़कों पर न फैले।

सुरक्षा और सुंदरता का समावेश

गांव में सुरक्षा के लिए सभी चौराहों और शासकीय कार्यालयों में सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं। विद्यालयों में भी सी.सी.टीवी, आरओ वॉटर, और बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया गया है। बच्चों को हाथ धुलाई और स्वच्छता की आदतों के प्रति जागरूक किया गया है।

कला के माध्यम से स्वच्छता का संदेश

गांव में कचरे से कलात्मक वस्तुएं बनाकर गांव की सुंदरता को बढ़ाया गया। इससे गांव में स्वच्छता के साथ कलात्मकता और सौंदर्य का भी समावेश हुआ, जो अन्य पंचायतों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है।

इंटरनेट में भी आत्मनिर्भर

डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए, ग्राम पंचायत खेड़ावदा को पूर्ण रूप से वाईफाई जोन बनाकर इन्टरनेट से कनेक्ट किया गया है एवं सभी चौराहों व शासकीय कार्यालयों पर सीसीटीवी केमरे लगाए गए हैं। खेड़ावदा आज एक आदर्श गांव का प्रतीक है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक गांव अपने प्रयासों से स्वच्छ, सुजल और आत्मनिर्भर बन सकता है। खेड़ावदा की यह पहल अन्य गाँवों के लिए एक मॉडल है और इसका ग्राम पंचायतों द्वारा भी अनुकरण किया जा रहा है।

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर, इटारसी का किया निरीक्षण

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएः मंत्री पटेल

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल द्वारा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर, इटारसी का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रक्षेत्र पर संचालित कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत संचालित बकरी पालन केंद्र एवं पशु आहार संयंत्र का निरीक्षण किया। मंत्री पटेल द्वारा प्रबंधक को प्रक्षेत्र की व्यस्थाओं की बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रक्षेत्र की खाली कृषि योग्य भूमि का उपयोग कर फार्म की आय बढाने के प्रयास किए जाएं। गेंहू, भूसा एवं साइलेज क्रय करने के संबंध में प्रबंध संचालक को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय किसानों को प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम दरों पर उक्त सामग्री क्रय की जाए। मंत्री पटेल ने प्रक्षेत्र पर कार्यरत श्रमिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और निराकरण के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने उन्नत कृषकों से बातचीत कर उनके अनुभव सुने। उन्होंने प्रक्षेत्र परिसर में पौध-रोपण भी किया। भ्रमण में मंत्री पटेल के साथ प्रबंध संचालक डॉ. राजू रावत, पूर्व प्रबंध संचालक डॉ. एचबीएस भदौरिया, प्रबंधक पशु प्रजनन प्रक्षेत्र डॉ. एलपी अहिरवार, एनकेबीसी प्रबंधक डॉ. पवन सिसोदिया, पशु आहार संयंत्र प्रबंधक डॉ. सुनील चौधरी, उन्नत कृषक शरद वर्मा, राजकुमार मेहतो, सोनू चौधरी, अन्य कृषक एवं श्रमिक उपस्थित रहे।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन, फसलों की नई प्रजातियों को बढ़ाया देने की जरुरतः निदेशक

बकरी पालन में तेजी से उभरता मप्र राज्य किसानों को बाजार तक जोड़ने की जरूरत

लहार (भिंड)। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, लहार पर रवी 2024-25 की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पिछले 6 माह की कार्य प्रगति तथा आगामी 6 माह के कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण केंद्र प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा किया गया। बैठक में देश के विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक, जिले के अधिकारियों, किसानों एवं केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा भाग लेकर सुझाव प्रस्तुत किए गए।

केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा पिछले छह माह-अप्रैल से सितंबर की प्रगति एवं अक्टूबर 2024 से मार्च-2025 तक किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक का आयोजन हाइब्रिड मोड में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. वायपी सिंह द्वारा सुझाव देते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र को जिले के ज्यादा से ज्यादा गांवों में पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले तकनीकी परीक्षण एवं प्रदर्शनों में फसलों की नई प्रजातियों को शामिल करने की आवश्यकता है। खरीफ मौसम में बाजरा ज्वार के साथ अन्य फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए। वहीं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश राज्य बकरी पालन में पांचवें स्थान पर

बैठक में विचार रखते हुए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम (मथुरा) के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनुपम कृष्ण दीक्षित ने कहा के मध्य प्रदेश बकरी पालन में तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य बकरी पालन में पांचवें स्थान पर आता है। उन्होंने बकरी पालन को व्यावसायिक स्तर पर करने की सलाह देते हुए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से अनुदान का लाभ उठाने के लिए आगे आकर बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का सुझाव रखा। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान (पूसा) नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विकास यादव ने कहा कि फसल उत्पादन और विस्तार के साथ किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज जरूरत किसानों को नए-नए बाजारों से जोड़ने की है, जिससे वह अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य ले सकें।

किसानों को मेड पर बहुवर्षीय चारा उगाने की जरूरत

कृषि महाविद्यालय इंदौर की सहायक प्राध्यापक डॉ. अर्पण उपाध्याय ने कहा कि डेरी पशुओं को वर्षभर हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए किसानों को मेड पर बहुवर्षीय चारा उगाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए किसानों को जागरूक करने का सुझाव दिया। आईसीएआर- अटारी, जोन 9, जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अजय राउत ने सुझाव देते हुए कहा कि तकनीकी परीक्षणों और प्रदर्शनों के परिणाम के साथ ही उनमें आने वाली समस्याओं को भी उजागर किया जाये। बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉ. प्रशांत गुप्ता, ग्वालियर की डॉ. अमिता शर्मा ने भी अपने विचार रखे। बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के डॉ. सुशील कुमार सिंह, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉ. अखिलेश सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, केवीके के डॉ. आरपीएस तोमर, डॉ. रूपेंद्र कुमार, डॉ. करणवीर सिंह, डॉ. नरेंद्र भदोरिया, डॉ. बीपीएस रघुवंशी, निशांत प्रभाकर, दीपेन्द्र शर्मा, परमेश सोनी, एनआरएलएम से अरुणा देवी, मनोज शिवहरे, महिला बाल विकास विभाग की सरिता शर्मा, विकास सिंह, कृषि विभाग से एके शाक्य, गोहद एफपीओ की बाली सिंह, विनोद दुबे, विनीत सिंह चंदेल, शुगम कुशवाहा, गिर्राज राजावत, मोनू सिंह राजावत, विजय शर्मा, अब्दुल रहमान आदि किसान और विभागों से जुड़े हुए लोगों द्वारा भाग लिया गया।

प्राकृतिक/ जैविक खेती अपनाने पर रहेगा फोकस

धार में नवाचारः 5 विकासखडं में चिया सीड्स की होगी खेती, किसानों को करेंगे प्रोत्साहित

धार। जागत गांव हमार

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) अंतर्गत गर्वनिंग बोर्ड की बैठक कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रियंक मिश्रा की मौजूदगी में की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशाल धाकड़ भी उपस्थित थे। आत्मा अंतर्गत खरीफ सीजन में किए गए कार्यों की समीक्षा एवं आगामी रबी सीजन में किए जाने वाली गतिविधियों का अनुमोदन किया गया। इस वर्ष नवाचार के रुप में जिले के धार, तिरला,नालछा, सरदारपुर एवं बदनावर विकासखंडों में चिया सीड्स की खेती करवाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। कृषकों को चिया सीड्स उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिले के निमाड़ अंचल में आने वाले विकासखंड मनावर, गंधवानी, उमरवन, कुक्षी, बाग, डही, निसरपुर में

नवाचार के लिए जीवामृत ट्यूब इकाई क्लस्टर ग्रामों में स्थापना कर प्राकृतिक/ जैविक खेती अपनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कपास बीज उत्पादक कार्यक्रम में किसानों की भागीदारी बढ़ाने एवं आत्मा अंतर्गत कृषक संगोष्ठी, कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण दल जैसी गतिविधियों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उप संचालक कृषि जीएस मोहनिया, परियोजना संचालक आत्मा कैलाश मगर आत्मा गर्वनिंग बोर्ड के अशासकीय सदस्य चंचल पाटीदार, नरेंद्र राठौड़, कैलाश वर्मा, मुकेशु, सुचित्रा बाई रामेश्वर, उप परियोजना संचालक आत्मा केएस झणिया, कम्प्यूटर प्रोग्रामर ताराचंद रावत भी उपस्थित थे।

नर्मदापुरम में शुरू हुआ देशी डिप्लोमा का 18वां बैच एग्रीकल्चर डीलर्स प्रशिक्षण

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

कृषि आदान विक्रेताओं के लिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर फॉर इनपुट डीलर्स का एक वर्षीय 18वां कम्बाइंड बेच का कृषि विज्ञान केंद्र बनखेड़ी में प्रारंभ हुआ। सत्र के दौरान डिप्लोमा कार्यक्रम में साप्ताहिक 40 कक्षाएं लगाई जाती हैं एवं 8 भ्रमण कराएं जाते हैं। इस तरह 48 सप्ताह के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को निपुण किया जाता है। कोर्स पूर्ण कर अंतिम परीक्षा पास करने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। देशी डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी परियोजना संचालक आत्मा जिला नर्मदापुरम हैं। 18वें बेच का नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केवीके बनखेड़ी हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में उप परियोजना संचालक आत्मा गोविन्द मीना, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संजीव कुमार गर्ग, कृषि वैज्ञानिक डॉ. लवेश कुमार चौरसिया, डॉ. आकांक्षा पांडे एवं देशी फेसिलिटेटर तोरण सिंह दांगी साथ ही प्रतिभागी उपस्थित थे।

व्यावसायिक डेयरी और बकरी पालन पर सरकार देगी 50 प्रतिशत तक अनुदान

भिंड। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक मैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम (मथुरा) उप्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ अनुपम कृष्ण दीक्षित ने बताया कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत किसानों को डेरी खोलने तथा बकरी पालन जैसे व्यवसाय करने हेतु बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान भारत सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। यह

योजना पूरे देश में लागू है और कोई भी किसान डेरी, बकरी पालन, सुकर पालन, मुर्गी पालन आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम 20 लाख अधिकतम प्रोजेक्ट की कास्ट के अनुसार 10 प्रतिशत मारजिन मनी लगाकर ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए इच्छुक किसानों को जिले के उपसंचालक पशुपालन से संपर्क करना होगा। इसके बाद प्रोजेक्ट फाइल तैयार होकर बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त होगा।

बिना किसी दुष्प्रभाव के बीमारी की जड़ पर वार करती है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति: वैद्य राजोरा

सदा सुहागन से शुगर कंट्रोल, इंसुलिन का पौधा कैंसर-बीपी में फायदेमंद

भोपाल । जागत गांव हमार

आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और इसका प्रादुर्भाव भारत में ही हुआ था, पर यह आज बहुत पिछड़ा हुआ है। हम अपने प्राचीन ज्ञान से ही संतुष्ट हैं और उसकी डींगे हांकते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई नया अनुसंधान और विकास नहीं करते हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक अलग 'आयुष मंत्रलय' बनाकर एक नई

शुरूआत जरूर की है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले लिखी गई चरक संहिता, सुस्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम नामक तीन प्राचीन किताबों को आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है। इसलिए इसका शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। यह बीमारी की जड़ पर वार करती है। भोपाल में रहने वाले वैद्य बीएस रजोरा का कहना है कि आयुर्वेद से कई असाध्य रोगों का इलाज संभव है। उनका दावा है कि इंसुलिन पौधे की जड़ी से कैंसर-ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट होता है। गुड़हल का फूल पथरी को खत्म करता है तो सदा सुहागन (सदाबहार) पौधे का फूल शुगर कंट्रोल करता है।

ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए गुड़हल के फूल की चाय

वैद्य बीएस रजोरा कहते हैं, गुड़हल औषधीय महत्व का पौधा है। इसके फूल की चाय बनाकर पीने से पथरी में आराम मिलता है। ब्लड भी प्यूरीफाई होता है। महिलाएं अगर इस चाय को पीती हैं तो उन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। गुड़हल के फूल को चबाकर खाने से व्यक्ति के शरीर में ताकत का इजाफा होता है। बाजार में गुड़हल के फूल का पाउडर हिबिस्कस पाउडर के नाम से मिलता है। वैद्य रजोरा ने बताया, ऐसे मरीज, जिन्हें हाई ब्लड शुगर की शिकायत है, वे सदा सुहागन पौधे के फूल को चबाकर खाएं। अलग से इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगी। लिवर जब इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तब डॉक्टर्स पेशेंट को इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। शुगर का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी नहीं है। इसे केवल जड़ी-बूटियों से नियंत्रित किया जा सकता है।

ये होते हैं चाय के फायदे: हिबिस्कस चाय को ब्लड प्रेशर कम करने के लिए प्रभावी माना गया है। अध्ययनों से पत चला है कि गुड़हल की चाय का सेवन करने से एलडीएल और ट्राय ग्लिसराइड का स्तर कम हो जाता है। गुड़हल की चाय गुड़हल के पौधे के चमकीले रंग के फूलों से बनाई जाती है। सूखी कलौंजी का उपयोग गुड़हल की चाय में किया जाता है, जिससे इसके स्वाद में न केवल ताजगी का अहसास होता है, बल्कि तीखापन भी आता है। एंटीऑक्सीडेंड के अलावा गुड़हल की चाय में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ट्रेस मिनरल की कुछ मात्रा पाई जाती है। यह हर्बल चाय बर्ड फ्लू के कुछ प्रकारों के खिलाफ प्रभावी साबित हुई है।

-उद्यानिकी फसलों से निलेश ने 37 लाख फायदा कमाया

नेट हाउस से बढ़ी निलेश की आय, 21 लाख 35 हजार रु. मिला मुनाफा

भोपाल। । जागत गांव हमार

झाबुआ जिले के मांडन गांव के किसान निलेश पाटीदार अब हर उस किसान के लिए एक प्रेरणा बन गये हैं, जो पारंपरिक खेती में सीमित होकर संघर्ष कर रहे हैं। निलेश के पास 18.750 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जहां वे सालों से पारम्परिक खेती कर रहे थे। लेकिन एक दिन उद्यानिकी विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से मिले सुझाव ने उनकी जिंदगी बदल दी। क्षेत्रीय अधिकारी ने उन्हें पारम्परिक खेती छोड़कर एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत संरक्षित खेती योजना का लाभ लेने और उद्यानिकी खेती अपनाने की सलाह दी। निलेश ने इस दिशा में हौले-हौले कदम बढ़ाए। सफलता भी मिलने लगी। अब बागवानी मिशन से निलेश के जीवन की बगिया में मिशन मोड पर मिठास आ गई है। उद्यानिकी खेती के लाभों को समझते हुए निलेश ने शुरु में एक एकड़ भूमि पर नेटहाउस का निर्माण कराया। पहली ही फसल में उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी खेती का दायरा बढ़ाया और धीरे-धीरे 3 और नेट हाउस बनवाए। इस वर्ष उन्होंने 3 एकड़ के नेट हाउस में देशी खीरा

और ककड़ी की खेती की। इससे उन्हें 1050 क्विंटल उत्पादन मिला। इस उपज को उन्होंने जयपुर और दिल्ली में 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा, जिससे उन्हें कुल 28 लाख 35 हजार आय हुई। खेती-बाड़ी का खर्चा निकालने के बाद उन्होंने इस नेट हाउस से करीब 21 लाख 35 हजार रुपये शुद्ध मुनाफा कमाया।

अमरूद की खेती में सफलता- नलेश ने अपने खेत में 4 एकड़ भूमि पर अमरूद के 4000 पौधे लगाए। इससे उन्हें 700 क्विंटल अमरूद का उत्पादन प्राप्त हुआ। उन्होंने उपज को बक्सों में पैकिंग कर दिल्ली में 4000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा। इससे निलेश को 28 लाख आय हुई। इस वर्ष पौधों को सहारा देने के लिए लोहे के एंगल और तार के स्ट्रक्चर बनाने में ही उन्होंने 12 लाख से अधिक पूंजी खर्च की। अमरूद की फसल से निलेश को 16 लाख शुद्ध मुनाफा हुआ।

नई शुरुआत, नई संभावनाएं

इन दोनों उद्यानिकी फसलों से निलेश ने कुल 37 लाख रुपये मुनाफा कमाया। इस मुनाफे से उन्होंने एक जेसीबी गाड़ी खरीद ली है और अब खेती के साथ-साथ जेसीबी व्यवसाय से भी अतिरिक्त आय ले रहे हैं। निलेश की प्रगतिशीलता से न केवल उनके परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि उन्होंने अन्य किसानों के सामने भी एक नजीर पेश की है। निलेश कहते हैं कि अगर सभी किसान भाई नये-नये तरीकों और उन्नत खेती तकनीकों को अपनाएं, तो वे भी उनकी तरह अपनी माली हालत मजबूत कर सकते हैं। संरक्षित (उद्यानिकी) खेती पद्धति से समृद्धि कैसे पाई जा सकती है, ये उन्होंने सीख लिया है।

लंपी स्किन डिसीज़: 1 लाख 24 हजार से अधिक पशुओं का किया टीकाकरण

नीमच। लम्पी स्किन डिसीज पशुओं की एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें शरीर पर गांठें उभर आती है। जो कि मच्छर, मक्खी आदि के काटने से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है एवं स्वस्थ पशु को संक्रमित पशु के सम्पर्क में हरा चारा, पीने के पानी के बर्तन आदि द्वारा भी बीमारी फैलती है। अत: बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। उप संचालक पशुपालन नीमच ने बताया, कि पशुपालन विभाग द्वारा इस वर्ष में 1 लाख 24 हजार 426 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है एवं टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है।

पशुपालन विभाग ने पशु पालकों से अनुरोध किया है, कि इस बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय टीकाकरण दल या कर्मचारी आने पर अपने पशुओं में टीकाकरण करवाएं एवं पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखने पर ऐसे पशुओं को अलग अपने बाड़े में रखें एवं किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। बीमारी के रोकथाम में सहयोग करें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था में सम्पर्क करें ।

कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी की 36वीं वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति बैठक आयोजित

कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी की 36वीं वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति बैठक

शिवपुरी। जागत गांव हमार

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि ग्वालियर के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी की 36वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से 08 नवम्बर 2024 को आयोजित हुई। उक्त बैठक में ऑनलाइन माध्यम से मुख्य अतिथि डॉ. शालिनी चक्रवर्ती प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अनु.प.-कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन 9 जबलपुर, विशिष्ट अतिथि डॉ. वायपी सिंह निदेशक विस्तार सेवाएं राविसिंकृविवि ग्वालियर, डॉ. वायडी मिश्रा, वैज्ञानिक (कृषि प्रसार) निदेशालय विस्तार सेवाएं रा.वि.सिं. कृविवि ग्वालियर थे।

कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार के निर्देशन में शुभारंभ एवं स्वागत करते हुए जिले के कृषि एवं संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख एवं उनके प्रतिनिधियों को वैज्ञानिक परामर्श समिति बैठक की गतिविधियों से अवगत कराया गया। जिसका विस्तार से पॉवर पाइंट प्रजेन्टेशन डॉ. एमके भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि

विज्ञान केन्द्र शिवपुरी द्वारा किया गया। जिसमें केन्द्र की विगत 6 माह के कार्यों का प्रस्तुतीकरण एवं आगामी 6 माह के किये जाने वाले कार्यों की योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। बैठक में बतौर कार्ययोजना सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञों एवं संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए जिसमें प्रमुख सुझाव टमाटर की और उन्नत प्रजातियों का परीक्षण, काले गेहूं एवं पोटेटो प्लांटर की उपयोगिता को बढ़ाने, मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण और करने, संसाधन संरक्षण तकनीकियों को और बढ़ावा दिया जिससे पर्यावरण प्रदूषण एवं पराली जलाने की प्रक्रिया को रोका जा सके इत्यादि रहे।

48 सदस्यों की सहभागिता रही

ऑफ लाइन माध्यम से केन्द्र के डॉ. जेसी गुप्ता, डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह, डॉ. एएल बसेड़िया, डॉ. लक्ष्मी, वैज्ञानिक, डॉ. एनके कुशवाहा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, विजय प्रताप सिंह शोध सहायक, सतेन्द्र गुप्ता कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल एवं जिले के कृषि एवं संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख, उनके प्रतिनिधियों डॉ. किरण रावत, एसएस घुरैया सहायक संचालक कृषि, बीएम मिश्रा सहायक संचालक उद्यान, प्रमोद गोयल शक्तिशाली महिला संगठन, रामगोपाल गुप्ता, जगदीश गिरी गोस्वामी प्रगतिशील कृषक एवं अन्यों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में आए सुझावों को समाहित कर सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करने का आश्वासन देते हुए आभार डॉ. जेसी गुप्ता वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी द्वारा किया गया। बैठक में कृषि विज्ञान केन्द्र के डॉ. नीरज कुमार कुशवाहा एवं आरती बंसल स्टेनो की तकनीकी कार्य में सक्रिय सहभागिता रही। बैठक में कुल 48 सदस्यों की सहभागिता रही।

26 नवंबर से 29 तक चार दिन हैदराबाद में पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा

एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री एक्सपो में होगी प्रोडक्शन-फीड पर चर्चा, जुटेंगे 50 देशों के लोग

तीन दिन तक हाईटेक्स एक्सपो सेंटर में एक्जीबीशन का आयोजन किया जाएगा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

हर साल हैदराबाद में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाता है। एक्सपो में करीब 50 देशों के पोल्ट्री एक्सपर्ट और कारोबारी जुटेंगे। इस दौरान पोल्ट्री सेक्टर में आई और आने वाली नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इस पर भी गहन चिंतन किया जाएगा कि कैसे पोल्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और फीड में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। साथ ही पोल्ट्री से जुड़ी बीमारियों पर भी खास चर्चा होगी। एक्सपो में 26 नवंबर, 2024 को नॉलेज डे का आयोजन किया जाएगा। वहीं तीन दिन तक हाईटेक्स एक्सपो सेंटर में एक्जीबीशन का आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो का आयोजन भारतीय पोल्ट्री उपकरण निर्माता संघ की ओर से पोल्ट्री इंडिया नाम से किया जाता है। इस बार एक्सपो की थीम अनलॉकिंग द पोल्ट्री पोटेंशियल रखी गई है।

एक्सपो में पोल्ट्री के लिए प्रोडक्ट तैयार करने वालीं और सर्विस देने वालीं करीब 400 कंपनियां अपने स्टॉल लगाएंगी। वहीं तीन दिन में 40 हजार से ज्यादा पोल्ट्री फार्मर और एक्सपर्ट के इस एक्सपो में आने की उम्मीद है। पोल्ट्री इंडिया के प्रेसिडेंट उदय सिंह ब्यास ने केन्द्र और राज्यों की सरकार से पोल्ट्री को मजबूती देने की अपील की है। उनका कहना है कि आज पोल्ट्री सेक्टर कई क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। देश की फूड सिक्योरिटी, युवाओं को रोजगार और देशवासियों के लिए जरूरी और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए न्यूट्रीशन पर काम कर रहा है। पोल्ट्री सेक्टर हर साल 100 करोड़ रुपए का योगदान देता है, लेकिन 1.35 लाख करोड़ की लागत वाला पोल्ट्री सेक्टर आज कई मुद्दों से जूझ रहा है। खासतौर पर पोल्ट्री फीड को लेकर सेक्टर की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। सोया मील और पोल्ट्री उपकरणों पर जीएसटी के बोझ से ये परेशानी और बढ़ रही है। अगर सरकार कीमतों को स्थिर करने, किफायती फीड सुनिश्चित करने और खासतौर से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लोन देने की सीमा का विस्तार करके लोन देने के नियमों तक आम पोल्ट्री किसान की पहुंच को आसान बनाना होगा।

पोल्ट्री को मजबूत बनाने के लिए ये भी हो रही मांग

- सोया मील और प्रोसेसिंग से जुड़ी मशीनरी पर जीएसटी में छूट दी जाए।
- पोल्ट्री फीड को कंट्रोल करने के लिए मक्का इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाए।
- पशु रोगों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक वैक्सीन आयात प्रोटोकॉल लागू हो।
- बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए स्कूली भोजन में अंडा शामिल किया जाए।
- डिमांड वाले देशों में पोल्ट्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 'फोकस सेक्टर' की जरूरत है।

हिल्सा निर्यात पर हटाया बैन

इधर, घरेलू बाजार की डिमांड पूरी करने और सीफूड एक्सपोर्ट में जान फूंकने के लिए मछली पालन और पकड़ने के काम में एक क्रांतिकारी पहल शुरू हो गई है। वक्त रहते ताजा मछलियां कम खर्च में बाजार तक पहुंच जाएं इसके लिए ड्रोन का ट्रॉयल शुरू हो गया है। इतना ही क्वालिटी का सीफूड एक्सपोर्ट हो सके इसके लिए भी समुद्र में ड्रोन भेजने की तैयारी हो रही है। इसी के चलते हाल ही में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोच्चि, केरल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। ये वर्कशॉप मछली पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन तकनीक के इसतेमाल पर आयोजित की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन ने देखी ड्रोन से मछलियों की सप्लाई और दूसरे काम भी देखे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार मछली पालन सेक्टर में परिवर्तन लाने और देश में नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक सुधार और विकास में हमेशा सबसे आगे रही है। बीते 10 साल में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 38.6 हजार करोड़ के निवेश किया है। कुरियन ने बताया कि मछली पालन से लेकर समुद्र में मछली पकड़ने में ड्रोन का कहां-कहां और क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए ड्रोन का ट्रॉयल शुरू हो गया है।

जेम पोर्टल पर बीज की 170 श्रेणियां लॉन्च

अब किसान ऑनलाइन मंगवा सकेंगे कई प्रकार के बीज

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

आगामी फसल सीजन से पहले बनाई गई, नई श्रेणियों में करीब 8,000 प्रकार के बीजों की किस्म शामिल हैं, जिन्हें देशभर में बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य शासी निकायों द्वारा खरीदे जाने का प्रावधान है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानि जेम पोर्टल पर बीज की 170 श्रेणियां लॉन्च की गई हैं। जिसका उद्देश्य किसानों की गुणवत्तापूर्ण कृषि और बागवानी बीजों तक पहुंच को आसान बनाना है। सरकारी एजेंसी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि आगामी फसल सीजन से पहले बनाई गईं, नई श्रेणियों में लगभग 8,000 प्रकार के बीज की किस्मों को शामिल किया गया है। जिन्हें देशभर में आगे प्रसार के लिए केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य शासी निकायों द्वारा खरीदा जा सकेगा। राज्य बीज निगमों और अनुसंधान निकायों सहित पक्षकारों के साथ परामर्श के बाद बनाई गई बीज श्रेणियां जीईएम पोर्टल पर बीज खरीदने के लिए एक तैयार रूपरेखा दे रही है। जिसमें मौजूदा नियम और शर्तों को शामिल किया गया है। इन नियम व शर्तों को भारत सरकार ने खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने को बनाया है।

सुविधाजनक बनाना है मकसद

पोर्टल पर बीज की नई श्रेणियां जोड़ना जीईएम की लंबी रणनीति का एक हिस्सा है। इस कदम का उद्देश्य दक्षता बढ़ाने पर जोर देने के साथ, निविदा प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करना, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना भी है, जबकि देश भर में विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी को सुविधाजनक बनाना भी प्रमुख उद्देश्य है।

उपयोग के लिए प्रोत्साहित

जीईएम की डिप्टी सीईओ, रोली खरे ने कहा है कि इसे विक्रेताओं को इन नई बीज श्रेणियों का फायदा मिलेगा और सरकारी निविदाओं में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए अपनी मांग के अनुसार सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बीज निगमों और राज्य निकायों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की लागत प्रभावी खरीद के लिए नई श्रेणियों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहन कर रहे हैं।

एफसीआई को 10700 करोड़ की मंजूरी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली। देश के किसानों को और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में अब तेजी देखने मिल सकती है। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है। एफसीआई के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके चलते फरवरी, 2023 में अधिकृत पूंजी 11,000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ हो गई। भारत सरकार की ओर से एफसीआई को सौगात मिली है। एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ की महत्वपूर्ण इक्विटी को मंजूरी दी है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत करेगी और इसके परिवर्तन के लिए की गई पहलों को एक बड़ा बढ़ावा देगी। एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्न भंडार के रखर खाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण और बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों को स्थिर रखने के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और अंततः भारत सरकार की सब्सिडी कम होगी। इस कदम पर सरकार की ओर से कहा गया है कि एमएसपी आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के प्रति सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता, किसानों को सशक्त बनाने में एक प्रयास का प्रतीक है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।
» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।
» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 9425048589

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)